(ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, अन्ध कल्याण सोसाइटी, जो कि इसकी मालिक थी, ने निर्माण कार्य पूरा नहीं किया। तत्कालीन उप राज्यपाल ने पट्टे को रद्द करने के आदेश दिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 24 मार्च, 1993 को अधूरे ढांचे का अधिकार शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया। लोक निर्माण विभाग से उस स्थान पर बाड़ लगाने का अनुरोध किया गया है।

(घ) और (ङ) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

Murder of Shri L.D. Arora AC, Customs and Excise

1162. SHRI CHATURANAN MISHRA :
SHRI GURUDAS DAS GUPTA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the murder of Shri L.D. Arora, Additional Collector of Customs and Excise, Allahabad Division;

(b) whether it is a fact that Mr. Arora had information about the activities of Memon brothers and that their men are involved in his murder;

(c) whether any investigation is being conducted into the incident; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Registration, investigation, detection of crime is the responsibility of the concerned State Government. The matter is under investigation by the CID of the U.P. Police.

नक्सलवाद की समस्या से संबंधित कार्य-योजना

1163. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूल चन्द मीणा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नक्सलवाद की समस्या मात्र कानून और व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे कई जटिल आर्थिक और सामाजिक कारण हैं;

(ख) क्या नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के समुचित विकास के लिए मध्य प्रदेश और अन्य सीमावर्ती राज्यों ने कोई योजना तैयार की है और इसे केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य-योजना के कार्यान्वियन हेतु राज्य प्रशासन को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी; और

(घ) यह वित्तीय सहायता कब तक दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश और अन्य प्रभावित राज्यों की सरकारों ने संबद्ध जिलों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक कार्य-योजना बनायी है। इस संबंध में इस मंत्रालय में हुए विचार-विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि प्रभावित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई कार्य-योजना पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जाएगा ताकि संबंधित राज्य इसे अपनी वार्षिक योजना प्रस्तावों में सम्मिलित कर सकें।

Revival of Legislative Council in the States

1164. SHRI S.S. AHLUWALIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many State Legislatures have passed resolu-